2019 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विश्लेषण

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जून, 2019 को संसद को संबोधित किया था।[1] अपने अभिभाषण में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की मुख्य नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया था। निम्नलिखित तालिका में 2019 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य विषयों और उन विषयों के संबंध में की गई पहल की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। 29 जनवरी, 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस नोट को तैयार किया गया है। आंकड़ों के स्रोत एंड नोट्स में दर्ज किए गए हैं।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

अर्थव्यवस्था और वित्त

नीतिगत प्राथमिकता: भारत जीडीपी के लिहाज से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सरकार 2024 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है।

सरकार भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब में तब्दील करने के लिए कार्य कर रही है।

मौजूदा स्थिति:

- **वृद्धि दर:** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी के लिहाज से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।[2] 2018-29 में 6.8% की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में जीडीपी के 5% की दर से बढ़ने का अनुमान है।[3] 2019-20 में जीडीपी के 2.9 ट्रिलियन USD होने का अनुमान है जोकि 2018-19 के अनंतिम अनुमान से 7.5% अधिक है।[3]

तालिका 1: कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि दर (% में)[4]

वृद्धि दर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कृषि	4.8	5.4	7.9	5	2.1
मैन्यूफैक्चरिंग	6.5	7.1	8	6.7	7.6
सेवा	9.6	9	8.5	8.6	7.6
जीडीपी	7.4	8	8.2	7.2	6.8

Note: Agriculture includes agriculture, forestry, and mining; manufacturing includes manufacturing, construction, and electricity and water supply; and services includes trade, transport, financial, real estate and defence services.

नीतिगत प्राथमिकता: मुद्रास्फीति निम्न स्तरीय है और राजकोषीय घाटा नियंत्रण में।

मौजूदा स्थिति:

- **मुद्रास्फीति:** 2016-2021 की अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए 4% का लक्ष्य रखा गया है (2% से 6% के बीच)।[5] 2019-20 की पहली तीन तिमाही में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति इस प्रकार थी: (i) 3.1% (अप्रैल-जून); (ii) 3.5% (जुलाई-

प्राची कौर
prachi@prsindia.org

30 जनवरी, 2020

	सितंबर); और (iii) 5.8% (अक्टूबर-दिसंबर)। 2019-20 की पहली तिमाही में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति इस प्रकार रही: (i) 1.7% (अप्रैल-जून); (ii) 3.5% (जुलाई-सितंबर); और (iii) 10.7% (अक्टूबर-दिसंबर)।[6]
	▪ **राजकोषीय घाटा:** एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीडीपी के 3% का लक्ष्य है। 2019-20 में इसके जीडीपी के 3.3% (7,03,760 करोड़ रुपए) पर रहने का अनुमान है।[6] नवंबर 2019 तक (2019-20 के आठ महीने) राजकोषीय घाटा 8,07,834 करोड़ पर रहा, जोकि जीडीपी का 3.8% है।[7,8]
	तालिका 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा[9]
	▪ **चालू खाता घाटा (सीएडी):** 2019-20 की पहली दो तिमाहियों में सीएडी (i) 14.3 बिलियन USD (अप्रैल-जून), और (ii) 6.3 बिलियन USD (जुलाई-सितंबर) था।[10,11]
	▪ **विदेशी व्यापार**: अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान भारत का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 0.9% बढ़कर 397.5 बिलियन USD हो गया।[12] जबकि आयात 5.8% गिरकर 455.1 बिलियन USD हो गया।
विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है।	▪ **विदेशी मुद्रा भंडार:** 10 जून, 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार पिछले एक वर्ष की तुलना में 16% बढ़ गया और 461 बिलियन USD पर पहुंच गया। पिछले वर्ष 11 जनवरी, 2019 तक यह आंकड़ा 397 बिलियन USD था।[13]
	तालिका 3: प्रत्येक वर्ष जनवरी तक विदेशी मुद्रा भंडार[13]
	▪ **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई):** 2019-20 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में एफडीआई 26 बिलियन USD पर पहुंच गया, जबकि 2018-19 और 2017-18 में इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा क्रमशः 22.7 बिलियन USD और 25.4 बिलियन USD का था।[14,15]

तालिका 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा[9]

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटा (जीडीपी के % के रूप में)	4.1%	3.9%	3.5%	3.5%	3.4%

तालिका 3: प्रत्येक वर्ष जनवरी तक विदेशी मुद्रा भंडार[13]

	जन-16	जन-17	जन-18	जन-19	जन-20
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन USD में)	349	360	414	397	461

भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट, 2018 ने 146 देशों के भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त करना संभव बनाया है। इनमें से 80 देशों के साथ सूचनाओं का ऑटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित किया गया है।	▪ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचना दी है कि दिसंबर, 2019 तक 66 मामलों में 51 घोषित अपराधी दूसरे कई देशों में फरार हो गए हैं।[16] सीबीआई 51 प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्रोसेस कर रही है जो विभिन्न चरणों में लंबित हैं। इन 66 मामलों में देश छोड़कर भागने वाले व्यक्तियों ने लगभग 17,947 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।[16] ▪ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने भगोड़े आर्थिक अपराधी एक्ट, 2018 के अंतर्गत 10 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित अदालत में आवेदन दायर किए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार नवंबर 2019 तक छह भगोड़े आर्थिक अपराधी अवैध तरीके से देश से फरार हुए हैं।[16] इसके अतिरिक्त ईडी ने आठ लोगों के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है।
इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण निपटारे में मदद की है।	▪ दिसंबर 2019 तक इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत 136 आवेदन दायर किए गए। इनमें से 9,653 मामलों (46%) में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिन्हें आईबीसी के पूर्व-प्रवेश चरण में निपटाया गया है।[17] 2,838 मामलों (13%) को कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस में स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 306 मामलों (1%) को अपील/समीक्षा/वापसी द्वारा क्लोज कर दिया गया है। 161 रिजॉल्व्ड मामलों में वसूली योग्य राशि 1.6 लाख करोड़ रुपए है।[17]
जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ 'एक देश, एक कर, एक बाजार' की अवधारणा सच्चाई बन गई। जीएसटी को अधिक सरल बनाने का प्रयास जारी रहेंगे।	▪ 2018-19 में केंद्र सरकार ने जीएसटी के जरिए 5.8 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया (अनंतिम वास्तविक) जोकि उस वर्ष के बजट अनुमान से 21% कम है।[9] 2019-20 में जीएसटी राजस्व 6.6 लाख करोड़ रुपए है, जोकि 2018-19 के लिए अनंतिम वास्तविक से 14% अधिक है।[8] नवंबर 2019 तक (2019-20 के आठ महीने) जीएसटी राजस्व की राशि 4 लाख करोड़ रुपए थी, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 4% अधिक है।[7]

निरंतर सुधार के साथ टैक्सेशन प्रणाली के सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में पांच लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर छूट प्रदान की गई है।	▪ वित मंत्रालय ने नवंबर 2017 में आयकर एक्ट, 1961 की समीक्षा करने और एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ▪ पांच लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को 100% कटौती प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में आयकर एक्ट में संशोधन किया गया था। इसका आकलन वर्ष 2020-21 है। 2018-19 में, व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए 5.4 करोड़ रिटर्न (यानी रिटर्न का 98%) में आय पांच लाख रुपए से कम थी।[18]
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 के स्थान पर 2019 में 77 हो गई है। सरकार भारत को दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल करना चाहती है।	▪ अक्टूबर 2019 में विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में 190 देशों में भारत की रैंकिंग 63 थी, जबकि पिछले वर्ष यह रैंक 77 थी।[19,20] ▪ रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुछ मापदंडों में बदलाव किए, जिसके कारण इसकी व्यापार रैंकिंग में वृद्धि हुई। इनमें व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट से जुड़े मुद्दे, सीमाओं के पार व्यापार करने और इनसॉल्वेंसी को रिज़ॉल्व करने से संबंधित परिवर्तन शामिल है।[20]
विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेश अभियान 'जन धन योजना' सफल रहा।	▪ प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रारंभ से 8 जनवरी, 2020 तक इस योजना के अंतर्गत 37.83 करोड़ खाते खोले गए (इसमें 2017-18 में खोले गए 5 करोड़ खाते भी शामिल हैं)। इनमें से 59% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। 1.12 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा की गईं और 29.8 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।[21,22]

तालिका 4: जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते[21]

	जन -17	जन -18	जन - 19	जन - 20
खोले गए खातों की संख्या (करोड़ में)	6.84	3.72	3.1	3.68
जमा की गई राशि (रुपए लाख करोड़ में)	0.67	0.74	0.89	1.12

Note: The data for Jan 2020 is updated till January 08, 2020.

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के अंतर्गत 400 से अधिक योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों के खातों में सीधी जमा हो गई।

2014 से 7.3 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डीबीटी ने अयोग्य लाभार्थियों को 1.4 लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण पर रोक लगाई और आठ करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को हटाया।

- 22 जनवरी, 2020 तक 430 योजनाओं और 56 मंत्रालयों की योजनाओं के अंतर्गत (2013 से) लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के जरिए 9.1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए।[23]

तालिका 5: डीबीटी के जरिए वितरित राशि (2014-20)[23]

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
डीबीटी के जरिए वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	38,926	61,942	74,689	1,90,871	3,29,796	2,08,824
डीबीटी लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)	22.8	31.2	35.7	124	129.2	143.3

Note: The data for 2019-20 is updated till January 22, 2020. From 2017-18, numbers include both cash and in kind transfers.

देश के लगभग 1.5 लाख डाकघरों को 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर गांव में बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों।

- सितंबर 2017 में 650 जिलों में पोस्टल बैंक स्थापित करके भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरू किया गया।[24] इसने 1.35 लाख बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स से अधिक को संभव बनाया है जिनमें से 1.1 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

गृह मामले, विदेशी मामले और रक्षा

अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सरकार ने घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को लागू करने का निर्णय लिया है। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) असम में अपडेट किया गया था और पूरा मसौदा 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया था।[25] 3,11,21,004 व्यक्तियों को अंतिम एनआरसी में शामिल करने के योग्य पाया गया। 19,06,657 व्यक्तियों को अंतिम एनआरसी में शामिल नहीं किया गया था (इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दावे प्रस्तुत नहीं किए)।[25] कोई भी व्यक्ति जो दावों और आपत्तियों के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- तालिका 6 में 2016 से 2018 तक भारतीय सीमाओं में घुसपैठ के कुल मामलों का उल्लेख है।

तालिका 6: भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ के मामले[26]

दर्ज मामले	बांग्लादेश	पाकिस्तान	नेपाल	म्यांमार	भूटान	चीन

2016	3	25	6	74	कोई नहीं	कोई नहीं
2017	कोई नहीं	21	3	99	कोई नहीं	कोई नहीं
2018	कोई नहीं	28	3	109	कोई नहीं	कोई नहीं

- नागरिकता (संशोधन) बिल, 2019 को 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया। विधेयक नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह प्रावधान करता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।[27]
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल, 2019 को 6 अगस्त, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। बिल में जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के लिए जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है।[28] जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और उसके लिए वह जो प्रशासक नियुक्त करेंगे, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा।
- तालिका 7 में 2016 से 2019 के बीच भारत में वामपंथी चरमपंथी हिंसक घटनाओं का उल्लेख है।

सरकार अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न के शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करते हुए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए और अपने निवासियों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्राथमिकता है, आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 2014 से 2019 तक इस दिशा में काफी सफलता मिली है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं।

तालिका 7: 2016-19 के बीच वामपंथी चरमपंथ के मामले[29]

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षाकर्मी
2016	1,048	65
2017	908	75
2018	833	67
2019	339	38

Note: Data for 2019 is up till June 15, 2019.

सरकार सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त होगा। सरकार मेक इन इंडिया के अंतर्गत आधुनिक हथियारों के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है।

- 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2019-20 में रक्षा बजट में पूंजी परिव्यय में 10% की वृद्धि हुई है। इसमें टैंक, नौसेना के जहाज एवं विमान निर्माण कार्य और मशीनरी पर व्यय शामिल हैं।

तालिका 8: रक्षा सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय: बजट आबंटन (करोड़ रुपए में) Error! Bookmark not defined.

	वास्तविक 2017-18	संशोधित अनुमान 2018-19	बजटीय अनुमान 2019-20
पूंजीगत परिव्यय	90,438	93,982	1,03,394

- 2016-17 से 2018-19 के बीच पूंजीगत अधिग्रहण से संबंधित 149 अनुबंधों पर अंतिम निर्णय लिया गया।[30] इनमें से रक्षा उपकरणों की खरीद के 91 अनुबंध भारतीय वेंडरों के थे।
- 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस के बीच एक समझौते के माध्यम से खरीदे गए थे, जिनमें से तीन विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं।[31] बोइंग कंपनी और अमेरिकी सरकार के साथ 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद का अनुबंध किया गया था, जिनमें से आठ हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी हो चुकी है।[32]

'वन रैंक वन पेंशन' के माध्यम से, पूर्व-सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया के रूप में 10,795 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।[33] तालिका 9 में ओआरओपी के कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण है।

तालिका 9: ओआरओपी के कार्यान्वयन की प्रगति[33]

	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
चुकाई गई राशि (करोड़ रुपए में)	2,862	5,370	2,563	10,795

Note: The data is updated till June 26, 2019.

उद्योग

सरकार 2024 तक भारत में 50,000 स्टार्ट-अप स्थापित करना चाहती है।

- 26 नवंबर, 2019 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा भारत में 25,115 स्टार्ट-अप मान्यता प्राप्त हैं।[34]

उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी कवरेज एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा।	▪ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना एमएसएमई क्षेत्र में उधारकर्ताओं को ऋण संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान करती है।[35] 2018-19 में इस योजना में 4,35,520 लाभार्थी थे और 30,169 करोड़ रुपए की संचयी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी।[35]
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 19 करोड़ ऋण स्वरोजगार के लिए वितरित किए गए हैं। 30 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार किया जाएगा।	**तालिका 10: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु उद्यमों को दिए गए ऋण[36]** (see table below)

तालिका 10: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु उद्यमों को दिए गए ऋण[36]

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मंजूर ऋणों की संख्या (लाख में)	349	397	481	599	374
अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	1,37,449	1,80,529	2,53,677	3,21,723	1,91,520
संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	1,32,955	1,75,312	2,46,437	3,11,811	1,85,858

Note: The data for 2019-20 is updated till January 17, 2020.

कृषि

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2014 से कुछ निर्णय लिए गए हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना, खाद्य प्रसंस्करण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देना और 'फसल बीमा योजना' और 'सॉयल हेल्थ कार्ड' प्रदान करना शामिल है।

- 2018-19 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,750 रुपए प्रति क्विंटल था जोकि 2019-20 में 3.7% बढ़कर 1,815 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। 2018-19 में गेहूं के लिए एमएसपी 1,840 रुपए प्रति क्विंटल था जोकि 2019-20 में 4.6% बढ़कर 1,925 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।[37]
- खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई। यह योजना किसानों को फसल खराब होने पर बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- **तालिका 11: 2016-17 से 2018-19 के दौरान पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन[38]**

वर्ष	नामांकित किसान	दावा करने वाले किसान	दावों का भुगतान (करोड़ रुपए में)
2016-17	5.81 करोड़	1.48 करोड़	16,662
2017-18	5.27 करोड़	1.74 करोड़	21,743
2018-19	5.64 करोड़	1.65 करोड़	18,921

किसानों को आय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के हर किसान तक पहुंचाया गया है। इस योजना के अंतर्गत तीन महीनों में किसानों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। योजना पर अनुमानित व्यय 90,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।	▪ पीएम-किसान योजना में लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2,000 रुपए की तीन किस्तें दी जाएंगी। कवरेज में वृद्धि के साथ सरकार को इस योजना में लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की उम्मीद थी। 2019-20 में अब तक 7.5 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त मिली है, 6.1 करोड़ को दूसरी किस्त मिली है और 3 करोड़ को तीसरी किस्त मिली है।[39] ▪ 2019-20 में, पीएम किसान योजना को 75,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। 13 दिसंबर 2019 तक वर्ष 2019-20 के लिए योजना के अंतर्गत 29,877 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।[40] 2018-19 में, योजना के अंतर्गत 6,005 करोड़ रुपए जारी किए गए (वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के विपरीत)।
60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की गई है।	▪ सितंबर 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन के भुगतान का प्रावधान करती है।[41] यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें किसानों का मासिक योगदान 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है। जनवरी 2020 तक, लगभग 19 लाख किसान लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है।[41] 2019-20 में इस योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।
सरकार 13,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ मवेशियों की बीमारियों के इलाज के लिए एक विशेष योजना शुरू करेगी।	▪ 2019-24 की अवधि के लिए योजना की कुल प्रस्तावित लागत 13,343 करोड़ रुपए है। योजना को 2019-20 में 2,683 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।[42]
ग्रामीण और शहरी विकास	
2022 तक प्रत्येक गरीब को पक्की छत और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।	▪ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 2022 तक बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को 2.95 करोड़ घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।[43] सामाजिक आर्थिक और जातिगत आधार पर जनगणना, 2011 के असार, 5.4 करोड़ परिवार बेघर हैं।[44]

तालिका 12: कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण लक्ष्य (लाख में)[45]

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	निर्मित आवास	निर्माण का %
2015-16	21.20	18.69	88%
2016-17	42.76	37.18	87%
2017-18	32.03	26.80	84%
2018-19	25.16	23.03	92%

2022 के बाद कोई गरीब खुले में शौच नहीं करेगा।

- तालिका 13 में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-ग्रामीण के अंतर्गत 2014-15 और 2019-20 के बीच निर्मित शौचालयों की संख्या को दर्शाया गया है।

तालिका 13: एसबीएम-ग्रामीण: शौचालय और घर (लाख में)[46,47]

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
निर्मित शौचालय	49	124	216	296	224	228
दायरे में आने वाले घर	58	125	218	300	224	16

Note: The data for 2019-20 is updated till January 27, 2020.

- 27 जनवरी, 2020 तक 6,03,175 गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है, जिनमें से 99.3% सत्यापित किए गए हैं।[48] तालिका 14 में ओडीएफ गांवों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 14: शौच मुक्त गांवों की संख्या (संचित)[48]

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
घोषित ओडीएफ गांव	1,82,482	3,48,994	5,56,232	6,03,175
सत्यापित ओडीएफ गांव	1,82,461	3,48,795	5,53,923	5,99,064

Note: The data for 2019-20 is updated till January 27, 2020.

शहरों और उपनगरों में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

- 2019-20 में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) को 7,300 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमानों (6,400 करोड़ रुपए) से 14% अधिक था।[49] इसी प्रकार 2019-20 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन को 6,450 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जो कि 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान (6,169 करोड़ रुपए) से 5% अधिक था।

	▪ स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 स्मार्ट शहरों द्वारा 2,05,018 करोड़ रुपए की 5,151 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से 1,49,512 करोड़ रुपए (73%) की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, और 23,170 करोड़ रुपए (11%) की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।[50] ▪ अमृत परियोजना आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बुनियादी ढांचागत सेवाओं और शासन संबंधी सुधारों के विकास पर केंद्रित है।[51] राज्यों को राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं 77,640 करोड़ रुपए की हैं।[52]
कई शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। निर्बाध गतिशीलता के लिए 'वन नेशन, वन कार्ड' की सुविधा शुरू की गई है।.	▪ नवंबर 2019 तक 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क हैं जो परिचालित या निर्माणाधीन हैं।[53] 2019-20 में केंद्र ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,152 करोड़ रुपए आबंटित किए, जो 2018-19 के लिए अनुमानित अनुमान (15,600 करोड़ रुपए) से 23% अधिक हैं।[49]
रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन के लेनदेन को रोकने के लिए रियल एस्टेट (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 2016 को पारित किया गया था।	▪ 31 दिसंबर, 2018 तक 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ (जिनमें 13 अंतरिम अथॉरिटीज़ हैं) की स्थापना की है और 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए हैं (जिनमें से 12 अंतरिम हैं)।[54] जुलाई 2019 तक 43,398 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रियल एस्टेट (रेगुलेशन और विकास) एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।[55,56]
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक गांवों में लगभग दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।	▪ 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की गई थी। इसके दो घटक हैं- पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई-ग्रामीण।

तालिका 15: कार्यक्रम के अंतर्गत बने घर (लाख में)[57,58]

पीएमएवाई	अनुमोदित घर	निर्मित घर	निर्माण का %
ग्रामीण	139	93	67%
शहरी	103	32	31%
कुल	242	125	52%

Note: The data is as of January 25, 2020.

परिवहन	
2022 तक हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।	**तालिका 16: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई (किलोमीटर में)**[59] (तालिका नीचे)
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है।	▪ अक्टूबर 2019 तक लगभग 10,699 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 255 सड़क परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 2,64,916 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ मंजूरी दी गई है।[60]
सागरमाला परियोजना के अंतर्गत तटीय इलाकों और आसपास के इलाकों में अच्छी सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है।	▪ पोर्ट कनेक्टिविटी के अंतर्गत 235 चिन्हित परियोजनाओं में से 35 (15%) पूरी हो चुकी हैं और 94 (40%) परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इन 235 परियोजनाओं की परियोजना लागत 2,35,528 करोड़ रुपए है।[61]
पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर दिया गया है।	▪ 2015 से 2019 तक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 17,065 करोड़ रुपए की लागत से 1,262 किलोमीटर सड़क बन चुकी है।[62] भारतमाला परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र में सुधार के लिए लगभग 5,301 किमी सड़क को मंजूरी दी गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत क्षेत्र में 9,034 करोड़ रुपए की लागत से 20,708 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।[63]
उड़ान योजना के अंतर्गत छोटे शहरों में हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।	▪ अक्टूबर 2019 तक क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के अंतर्गत शहरों को जोड़ने वाली उड़ानों को शुरू करने के लिए 106 हवाई अड्डों और 31 हेलिपोर्ट्स की पहचान की गई है। आरसीएस उड़ानों के लिए 40 चालू हवाई अड्डे हैं। 706 स्वीकृत आरसीएस मार्गों में से 232 को चालू कर दिया गया है।[64,65]

तालिका 16: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई (किलोमीटर में)[59]

वर्ष	लक्षित लंबाई	निर्मित सड़कों की लंबाई	निर्माण का %
2015-16	33,649	35,155	104%
2016-17	48,812	47,447	97%
2017-18	51,000	28,844	57%
2018-19	57,700	49,041	85%
2019-20	50,097	13,475	27%

Note: Data for 2019 is as of January 25, 2020.

ऊर्जा

2022 तक हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन और बिजली उपलब्ध होगी।

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत लगभग 2.64 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे।[66] सितंबर 2019 के दौरान 18 राज्यों में के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के दौरान बिजली की आपूर्ति का औसत 20 घंटे से अधिक था।[67]
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक आठ करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 7.2 करोड़ कनेक्शन (90%) जारी किए गए हैं।[68] इसके अतिरिक्त देश में एलपीजी कवरेज मई 2016 में 62% से बढ़कर मार्च 2019 में 94% हो गया है।

बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

तालिका 17: सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड उत्पादन क्षमता[69]

	लक्ष्य (2022 तक)	इंस्टॉल्ड उत्पादन क्षमता (दिसंबर 2019 तक)	इंस्टॉल्ड लक्षित क्षमता का %
रीन्यूएबल एनर्जी	175 गिगावॉट	84.4 गिगावॉट	48.2%
जिसमें सोलर एनर्जी	100 गिगावॉट	32.5 गिगावॉट	32.5%

वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

- भारी उद्योग विभाग ने मार्च 2019 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) इंडिया योजना का चरण- दो शुरू किया। यह चरण 10,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय समर्थन के साथ तीन साल की अवधि के लिए है।[70] इसमें से 1,000 करोड़ रुपए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए निर्धारित किए गए हैं।

शिक्षा और खेल

सरकार ने समाज के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है।

- जनवरी 2019 में सरकार ने संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) एक्ट, 2019 पारित किया जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को लागू किया है।[71]

सरकार 2024 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या को 1.5 गुना बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसमें दो करोड़ सीटें शामिल होंगी।	▪ सरकार ने 158 केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त 2,14,766 सीटों के सृजन के लिए 4,315 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।[72]
दुनिया के शीर्ष 500 शिक्षण संस्थानों में अपनी जगह बनाने हेतु भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन देश भर के लगभग 9,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना का प्रयास कर रही है। 102 विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अटल इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।	▪ कुछ संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट संस्थानों का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय को उम्मीद है कि ये संस्थान अगले 10 वर्षों में दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में शुमार होंगे।[73] इस स्थिति को हासिल करने के लिए ऐसे संस्थानों को विदेशी विद्यार्थियों का दाखिला करने, फीस तय करने और विदेशी फैकेल्टी को नौकरी देने हेतु अधिक स्वायत्तता दी जा रही है। नवंबर 2019 तक सरकार ने 10 निजी संस्थानों और आठ सरकारी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चुना है।[74] ▪ 27 जनवरी, 2020 तक देश में 5,441 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं।[75] नवंबर 2019 तक मिशन ने 38 अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों को अनुदान दिया है।[76]
राज्य और जिला स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को विस्तार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 2,500 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह सुविधा हर साल 2,500 नए खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाएगा।	▪ 2019-20 में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 601 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो 2018-19 के संशोधित अनुमानों (317 करोड़ रुपए) से 90% अधिक था।[77] 2018-19 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 1,518 खिलाड़ियों का चयन किया गया जिनमें से 625 इसमें शामिल हुए।[78] नवंबर 2019 तक योजना के अंतर्गत 2741 एथलीटों की पहचान की गई है, जिनमें से 1388 एथलीटों ने प्रशिक्षण लिया है।[79] ▪ नवंबर 2019 तक, 173 खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इस योजना के अंतर्गत 581 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।[80]

महिला एवं बाल विकास

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को कठोर बनाया गया है और दंड संबंधी नए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिंग आधारित अपराध शामिल हैं, जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, शील भंग करने के इरादे से हमला और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता।

तालिका 18: 2016 और 2017 के बीच महिलाओं के साथ अपराध[81]

वर्ष	घटनाएं	प्रति लाख महिला पर अपराध
2016	3,38,954	55.2
2017	3,59,849	57.9

देश में हर बहन और बेटी के लिए समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए तीन तलक और निकाह-हलाला जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन महत्वपूर्ण है।

- संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल, 2019 को 30 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया जो तलाक कहने, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, को निष्प्रभावी और अवैध बनाता है।[82]

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या को कम किया है और देश के कई जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है।

- 2019-20 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 280 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। ध्यान दें कि यह 2018-19 के लिए संशोधित और बजट अनुमान के समान है।[83] पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना की वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका 19 में दिया गया है।

तालिका 19: बीबीबीपी की वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)[84,85]

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आबंटित	75	43	200	280	280
जारी	59	29	169	245	34
जारी राशि का %	79%	67%	85%	88%	12%

Note: The data for 2019-20 is updated till December 9, 2019.

स्वास्थ्य

50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। जून, 2019 तक 26 लाख रोगियों ने इस योजना के अंतर्गत उपचार का लाभ उठाया था।

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2019-20 में 6,400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। नवंबर 2019 तक 13.6 करोड़ लाभार्थी परिवार योजना के अंतर्गत आते हैं।[86]

	▪ नवंबर 2019 तक योजना के अंतर्गत 54.85 लाख दावे किए गए हैं और दावे की राशि 7,609 करोड़ रुपए है।
2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। 2019 तक ऐसे लगभग 18,000 केंद्रों का संचालन किया गया है।	▪ 2019-20 में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को 1,600 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह 2018-19 के संशोधित अनुमानों से 33% की वृद्धि थी।Error! Bookmark not defined. नवंबर 2019 तक देश भर में 24,070 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र चालू हैं।[87]
जल और पर्यावरण	
वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए 102 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है।	▪ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जनवरी, 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक $PM_{2.5}$ और PM_{10} को 20-30% तक कम करना है (2017 स्तरों की तुलना में)।[88] कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नॉन अटेनमेंट वाले शहरों की पहचान करने में सक्षम बनाता है यानी ऐसे शहर जो अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन नहीं करते। ▪ उसने 102 नॉन अटेनमेंट शहरों को चिन्हित किया जहां 2011-15 की अवधि के दौरान परिवेशी वायु गुणवत्ता ने निरंतर निर्धारित मानदंडों को पार कर लिया है।[89] यह देखा गया कि इनमें से अधिकतर शहरों में PM_{10} का स्तर निर्धारित मानदंडों को पार कर गया।[90] इसके अतिरिक्त 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी परिवेशी वायु प्रदूषण डेटाबेस के अनुसार, $PM_{2.5}$ के स्तर के लिहाज से विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं।[91] ▪ 2019 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 लाख से ज्यादा की आबादी और $90 \mu g/m^3$ से अधिक के PM_{10} स्तर वाले 28 शहरों को 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आबंटित की है।[92]

जल संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए जलशक्ति मंत्रालय बनाया गया है। 2022 तक गंगा नदी निर्बाध और प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत सरकार गंगा नदी में अपशिष्टों को छोड़ने वाले नालों को बंद करने के अभियान में तेजी लाएगी।	▪ जल शक्ति मंत्रालय जून, 2019 में दो विभागों के साथ बनाया गया था: (i) पेयजल एवं स्वच्छता, और (ii) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प।[93] तालिका 20 में पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय बजट में मंत्रालय के आबंटनों को प्रदर्शित किया गया है। **तालिका 20: जल शक्ति मंत्रालय का बजट अनुमान (करोड़ रुपए में)[94]** (see table below) Note: RE is Revised Estimate; BE is budget Estimate ▪ तालिका 21 में पिछले तीन वर्षों के दौरान नमामि गंगे योजना के आबंटनों को प्रदर्शित किया गया है। **तालिका 21: नमामि गंगे के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)[95]** (see table below)
वन और वृक्षों के आवरण में 1% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या भी 692 से बढ़कर 868 हो गई है।	▪ 2017 में पिछले आकलन की तुलना में 2019 में वन क्षेत्र में 0.6% और वृक्ष आवरण में 1.3% की वृद्धि हुई है।[96]
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
सरकार चंद्रयान 2 को लॉन्च करना चाहती है जो चंद्रमा तक पहुंचने वाला भारत का पहला एयरक्राफ्ट होगा। 2022 तक गंगायान के अंतर्गत पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य है।	▪ चंद्रयान 2 को 22 जुलाई, 2019 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया और उसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया लेकिन वह सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा।[97] 2008 में चंद्रयान 1 के बाद

तालिका 20: जल शक्ति मंत्रालय का बजट अनुमान (करोड़ रुपए में)[94]

विभाग	वास्तविक (17-18)	संशोधित (18-19)	बजटीय (19-20)	परिवर्तन का % (संशोधित से बजटीय)
जल संसाधन	5,313	7,613	8,245	8.3%
पेय जल	23,939	19,993	20,016	0.1%
कुल	29,252	27,606	28,261	2.4%

तालिका 21: नमामि गंगे के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)[95]

योजना	वास्तविक (17-18)	बजटीय (18-19)	संशोधित (18-19)	बजटीय (19-20)
नमामि गंगे	700	2,300	750	750

	यह भारत का चांद पर जाने वाला दूसरा अभियान था।[97] परियोजना के लिए स्वीकृत लागत (लॉन्च लागत को छोड़कर) 603 करोड़ रुपए थी।[98] ▪ गगनयान कार्यक्रम के लिए अपेक्षित कुल धनराशि लगभग 10,000 करोड़ रुपए है।[99]

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

[1] President's Address 2019, https://presidentofindia.nic.in/writereaddata/Portal/Speech/Document/683/1_sp200619.pdf.

[2] GDP: current prices, International Monetary Fund data mapper, last accessed on January 27, 2020, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

[3] "First Advance Estimates of National Income: 2019-20", Press Information Bureau, Ministry of Statistics and Program Implementation, January 7, 2020, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=197299.

[4] Annual and Quarterly Estimates of GDP at constant prices, 2011-12 series, National Accounts Data, Ministry of Programme and Statistics Implementation, http://www.mospi.gov.in/data.

[5] Overview-Monetary Policy, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2752.

[6] Medium Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/mtfpcfpss.php.

[7] Monthly Accounts for November 2019-20, Union Government Accounts, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, http://www.cga.nic.in/MonthlyReport/Published/11/2019-2020.aspx.

[8] Union Budget at a Glance, 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag1.pdf.

[9] Provisional Accounts for 2018-19, Union Government Accounts, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, http://www.cga.nic.in/MonthlyReport/Published/3/2018-2019.aspx.

[10] "Developments in India's Balance of Payments during the first quarter of 2019-20", Reserve Bank of India, Press Release, September 30, 2019, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=48273#.

[11] "Developments in India's Balance of Payments during the second quarter of 2019-20", Reserve Bank of India, Press Release, December 31, 2019, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49010.

[12] "India's Foreign Trade: December 2019", Press Information Bureau, Ministry of Commerce and Industry, January 15, 2020, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=197443.

[13] RBI Database, https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home.

[14] Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2019, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_September2019_01January2019.pdf.

[15] Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2018, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_1February2019.pdf.

[16] Rajya Sabha Unstarred Question No. 1664, Ministry of Finance, December 3, 2019, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Questions/QResult.aspx.

[17] "Year End Review – 2019 of Ministry of Corporate Affairs", Press Information Bureau, Ministry of Corporate Affairs, December 15, 2019, https://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1596523.

[18] Income Tax Return Statistics, Assessment Year 2018-19, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, October 2019, https://www.incometaxindia.gov.in/Documents/Direct%20Tax%20Data/IT-Return-Statistics-Assessment-Year-2018-19.pdf.

[19] 'Doing Business 2020', World Bank, http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf.

[20] 'Doing Business 2019', World Bank, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf.

[21] Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Archive, last accessed on January 22, 2020, https://www.pmjdy.gov.in/Archive.

[22] Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Progress Report, last accessed on January 22, 2020, https://www.pmjdy.gov.in/account.

[23] Direct Benefit Transfer, Government of India, last accessed on January 22, 2020, https://dbtbharat.gov.in/.

[24] Unstarred Question No. 795, Lok Sabha Questions, Ministry of Communications, June 26, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/171/AU795.pdf.

[25] Publication of final NRC on August 31, 2019, Office of State Coordinator, NRC, August 31, 2019, http://www.nrcassam.nic.in/pdf/English%20-Press%20Brief%2031st%20August%202019.pdf.

[26] "Cross Border Infiltration", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, February 5, 2019, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=188076.

[27] Citizenship (Amendment) Bill, 2019, https://prsindia.org/billtrack/citizenship-amendment-bill-2019.

[28] Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019, https://prsindia.org/billtrack/jammu-and-kashmir-reorganisation-bill-2019.

[29] "Steady decline in casualties in Naxal Attacks", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, July 17, 2019, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579194.

[30] Unstarred Question No, 476, Lok Sabha Questions, Ministry of Defence, November 20, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU476.pdf.

[31] "Rafale Jet", Press Information Bureau, Ministry of Defence, November 20, 2019, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=194706.

[32] "Induction of AH-64E Apache Attack Helicopter", Press Information Bureau, Ministry of Defence, September 3, 2019https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1583956.

[33] Starred Question No, 68, Lok Sabha Questions, Ministry of Defence, June 26, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/171/AS68.pdf.

[34] Unstarred Question No. 2587, Lok Sabha Questions, Ministry of Commerce and Industry, December 4, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU2587.pdf.

[35] Unstarred Question No, 5405, Lok Sabha Questions, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, July 25, 2019 ,http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/171/AU5405.pdf.

[36] Pradhan Mantri Mudra Yojana, Ministry of Finance, last accessed on January 17, 2020, https://www.mudra.org.in/.

[37] Minimum Support Prices Recommended by CACP and Fixed by Government, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, October 24, 2019, https://cacp.dacnet.nic.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=42&KeyId=681.

[38] Unstarred Question No. 3489, Lok Sabha Questions, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, December 10, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU3489.pdf.

[39] PM-KISAN Dashboard, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, as on January 26, 2020, https://www.pmkisan.gov.in/StateDist_Beneficiery.aspx.

[40] Unstarred Question No. 2899, Rajya Sabha Questions, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 13, 2019.

[41] "Year End Review 2019 - Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, January 7, 2020, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=197296.

[42] Foot and Mouth Diseases in Livestock", Ministry of Fisheries, Press Information Bureau, Animal Husbandry and Dairying, June 21, 2019, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1575278.

[43] "Rural Beneficiaries under PMAY", Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, August 6, 2018, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1541753.

[44] "Government committed to provide houses to all deprived sections", Press Release, Ministry of Rural Development, last accessed on January 26, 2020, https://rural.nic.in/press-release/government-committed-provide-houses-all-deprived-sections.

[45] PMAY-G MIS: High level physical progress report, Ministry of Rural Development, last accessed on January 26, 2020, https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/physicalprogressreportPhaseWise.aspx.

[46] Household Toilet Coverage Across India, Swachh Bharat Mission, Ministry of Jal Shakti, last accessed on January 27, 2020, http://sbm.gov.in/sbmdashboard/IHHL.aspx.

[47] Swachh Bharat Mission Target Vs Achievement On the Basis of Detail entered, Swatch Bharat Mission Gramin, Ministry of Jal Shakti, last accessed on January 26, 2020, https://sbm.gov.in/sbmReport/Report/Physical/SBM_TargetVsAchievementWithout1314.aspx.

[48] ODF Villages Across India, Swachh Bharat Mission, Ministry of Jal Shakti, last accessed on January 27, 2020, http://sbm.gov.in/sbmdashboard/ODF.aspx.

[49] Demand No. 56, Ministry of Housing and Urban Affairs, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe56.pdf.

[50] Unstarred Question No. 1693, Lok Sabha Questions, Ministry of Housing and Urban Affairs, November 28 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU1693.pdf.

[51] Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 24, 2020, http://mohua.gov.in/cms/amrut.php.

[52] Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 24, 2020, http://amrut.gov.in/content/.

[53] Unstarred Question No. 909, Lok Sabha Questions, Ministry of Housing and Urban Affairs, November 21, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU909.pdf.

[54] "Year Ender-Ministry of Housing & Urban Affairs-8-Final 2018:", Ministry of Housing and Urban Affairs, Press Information Bureau, January 27, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1557895.

[55] Unstarred Question No. 1815, Lok Sabha Questions, Ministry of Housing and Urban Affairs, November 28, 2019, http://loksabhaph.nic.in/Questions/QResult15.aspx?qref=8142&lsno=17.

[56] Unstarred Question No. 2052, Lok Sabha Questions, Ministry of Housing and Urban Affairs, July 4, 2019, http://loksabhaph.nic.in/Questions/QResult15.aspx?qref=2303&lsno=17.

[57] Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, Ministry of Rural Development, last accessed on January 27, 2020, https://www.iay.nic.in/netiay/home.aspx.

[58] Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 27, 2020, https://pmay-urban.gov.in/.

[59] Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Ministry of Rural Development, last accessed on January 27, 2020, http://omms.nic.in/.

[60] Unstarred Question No. 1668, Lok Sabha Questions, Ministry of Road Transport and Highways, November 28, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU1668.pdf.

[61] Projects under Sagarmala, Ministry of Shipping, last accessed on January 20, 2020, http://sagarmala.gov.in/projects/projects-under-sagarmala.

[62] "Road and rail connectivity in North Eastern Region", Press Information Bureau, Ministry of Development of North-East Region, July 17 2019, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579066.

[63] "Special Accelerated Road Development Programme for Development of Road Network in the North Eastern States", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, February 5, 2013, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=92040.

[64] "Ministry of Civil Aviation Launches Round 4 of RCS- UDAN", Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, December 3, 2019, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=195351.

[65] "Functional routes under UDAN rises to 186", Ministry of Civil Aviation, Press Information Bureau, July 18, 2019, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1579405.

[66] Lok Sabha Unstarred Question No. 2881, Ministry of Power, December 5, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU2881.pdf.

[67] Lok Sabha Starred Question No. 73, Ministry of Power, November 21, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AS73.pdf.

[68] Report of the Comptroller and Auditor General of India on Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Performance Audit, No. 14 of 2019, Ministry of Petroleum and Natural Gas, December 11, 2019, https://cag.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Report_No_14_of_2019_Performance_Audit_of_Pradhan_Mantri_Ujjwala_Yojana_Ministry_of_Petroleum_and_Natural_Gas_0.pdf.

[69] Year-End Review 2019, Ministry of New and Renewable Energy, Press Information Bureau, Jan 9, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1598948.

[70] "Promotion of Electric Vehicles", Press Information Bureau, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, July 2, 2019, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1576608.

[71] "Economically Weaker Sections (EWS) Bill", Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Women Empowerment, July 9 ,2019, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1577969.

[72] Unstarred Question No. 2295, Lok Sabha Questions, Ministry of Human Resource Development, July 8, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/171/AU2295.pdf.

[73] Unstarred Question No. 1048, Lok Sabha Questions, Ministry of Human Resource Development, December 17, 2018,http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/16/AU1048.pdf.

[74] Unstarred Question No. 44, Lok Sabha Questions, Ministry of Human Resource Development, November 18, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU44.pdf.

[75] Atal Innovation Mission, Ministry of Planning, last accessed on January 27, 2020, https://aim.gov.in/hubs-of-innovation.php.

[76] Unstarred Question No. 1419, Lok Sabha Questions, Ministry of Planning, November 27, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU1419.pdf.

[77] Demand No. 100, Ministry of Youth Affairs and Sports, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe100.pdf.

[78] 311th Report on Khelo India Scheme, Standing Committee on Human Resource Development, Rajya Sabha, December 12, 2019, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/123/311_2019_12_21.pdf.

[79] "Khelo India Programme", Ministry of Youth Affairs and Sports, Press Information Bureau, November 25, 2019, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1593391.

[80] "Khelo India Projects", Ministry of Youth Affairs and Sports, Press Information Bureau, November 25, 2019, https://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1593393.

[81] National Crime Records Bureau, 2016, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/Crime%20Statistics%20-%202016.pdf; National Crime Records Bureau, 2017, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2017/cii2017.html.

[82] "Parliament passes the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, July 30, 2019, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1580792.

[83] Demand No. 99, Ministry of Women and Child Development, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe99.pdf.

[84] Unstarred Question No. 1137, Lok Sabha Questions, Ministry of Women and Child Development, June 28, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/171/AU1137.pdf.

[85] Unstarred Question No. 4149, Lok Sabha Questions, Ministry of Women and Child Development, December 13, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU4149.pdf.

[86] Unstarred Question No. 1066, Lok Sabha Questions, Ministry of Health and Family Welfare, November 22, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU1066.pdf.

[87] Unstarred Question No. 1923, Lok Sabha Questions, Ministry of Health and Family Welfare, November 29, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU1923.pdf.

[88] "Government launches National Clean Air Programme (NCAP)", Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, January 10, 2019, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=187400.

[89] Lok Sabha Unstarred Question No. 1181, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, June 28, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/171/AU1181.pdf.

[90] National Air Quality Monitoring Programme Findings, Central Pollution Control Board, http://cpcbenvis.nic.in/air_pollution_main.html#.

[91] Unstarred Question No. 2154, Rajya Sabha Questions, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, August 6, 2018, https://pqars.nic.in/annex/246/Au2154.pdf.

[92] Unstarred Question No. 3211, Rajya Sabha Questions, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, July 22, 2019, https://pqars.nic.in/annex/249/Au3211.pdf.

[93] Organizational history of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, last accessed of January 13, 2020, http://mowr.gov.in/about-us/history.

[94] Demand no. 61, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe61.pdf; Demand no. 60, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe60.pdf.

[95] Demand no. 60, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe60.pdf.

[96] Executive Summary, India State of Forest Report, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, December 2019, http://fsi.nic.in/isfr19/vol1/executive-summary.pdf.

[97] "GSLV MkIII-M1 Successfully Launches Chandrayaan-2 spacecraft", Press Information Bureau, Department of Space, July 22,2019, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192082.

[98] "Launch of Chandrayaan – II", Press Information Bureau, Department of Space, November 22, 2019, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1592495.

[99] "ISRO to send first Indian into Space by 2022", Press Information Bureau, Department of Space, August 28, 2018, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183103.